RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 114
दि. 24.08.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष, डॉ. बलराम जाखड़ की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष, डॉ. बलराम जाखड़ की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश; संसद सदस्यों; पूर्व सदस्यों और लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह ने डॉ. जाखड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डॉ. जाखड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी 25-26 अगस्त को गुजरात दौरे पर : राजस्व, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के 1218 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट देंगे

- प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में विद्युत वितरण से जुड़ी 1122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, 4.25 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 96 करोड़ रुपए के खर्च से आकार लेने वाले राजस्व विभाग के दो अत्याधुनिक भवनों का शिलान्यास करेंगे
- अहमदाबाद : विद्युत वितरण के लिए 608 करोड़ रुपए के खर्च से भूमिगत सिस्टम तैयार, 2.01 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
- मेहसाणा : आधुनिक और भूमिगत विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 1.36 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ
- गांधीनगर में भूमिगत विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए 178 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार, 86,014 उपभोक्ता होंगे लाभान्वित

गांधीनगर, 23 अगस्त 2025 : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे और इस दौरान वे उत्तर गुजरात में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग की 1122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) और गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीईटीसीओ-गेटको) के अंतर्गत अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर जिलों में पांच मुख्य विद्युत वितरण परियोजनाएं शामिल हैं। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से 4.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, वे 96 करोड़ रुपए के खर्च से आकार लेने वाले राजस्व विभाग के दो अत्याधुनिक भवनों का शिलान्यास करेंगे।

अहमदाबाद : विद्युत वितरण के लिए 608 करोड़ रुपए के खर्च से भूमिगत सिस्टम तैयार

प्रधानमंत्री उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उसे भारत सरकार रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) और नॉर्मल डेवलपमेंट (एनडी) स्कीम के हिस्से के रूप में क्रियान्वित किया गया है। अहमदाबाद में 608 करोड़ रुपए की लागत से ओवरहेड बिजली के समग्र ढांचे को भूमिगत किया गया है, जिससे 2,00,593 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होगा।

गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को बताया दुर्योधन, 'राजा बन गए तो महाभारत होगा'

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गयाजी रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। दूसरी ओर वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू को खूब सुनाया है। केंद्रीय मेंत्री ने कहा कि लालू खुद धृतराष्ट्र बन गए हैं और तेजस्वी दुर्योधन हैं।

गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व डिप्टी सीएम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, 'लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र हैं और और तेजस्वी यादव दुर्योधन हैं। जैसे दुर्योधन का राजा बनने का सपना अधूरा रह गया, वैसे ही तेजस्वी की गद्दी की चाहत पूरी नहीं होगी। बिहार ने जंगलराज के परिणाम भुगते हैं और दोबारा इसे स्वीकार नहीं करेगा।'

बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित हैं। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा में व्यस्त हैं। इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और डीएमके भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इधर नीतीश कुमार और बीजेपी भी लगातार नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं।

इन सबके बीच नेताओं की बयानबाजी का दौर भी चल रहा है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद हर हाल में चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने।

भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है: प्रधानमंत्री

सुधार युवाओं और स्टार्टअप्स को नई संभावनाओं की तलाश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत 140 करोड़ भारतीयों के कौशल और प्रतिभा से प्रेरित होकर अंतरिक्ष की दुनिया में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। इससे युवाओं, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को नई संभावनाओं की तलाश करने और भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में देश अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। श्री मोदी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा और भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की उपलब्धियों के बारे में MyGovIndia के थ्रेड पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा;

'140 करोड़ भारतीयों के कौशल से प्रेरित होकर, हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। और, हम इससे भी आगे बढ़ेंगे!

#NÔtianalSpaceDay'

'हमारी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न सुधार शुरू किए हैं। इससे युवाओं, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को नए क्षेत्रों की खोज करने और भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

बदल गए प्रो कबड्डी लीग में कई नियम, इस बार रोमांचक होगा टूनार्मेंट

प्रो कबड्डी लीग ने सीजन 12 के लिए फॉर्मेट में महत्वपूर्ण प्रारूप परिवर्तनों की घोषणा की है। इसके माध्यम से एक धांसू लीग चरण और नए प्लेऑफ ढाँचे की शुरूआत की गई है, जो प्रतिस्पर्धा को रोमांचक कबड्डी एक्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगामी सीजन 29 अगस्त से शुरू होगा और इसके मैच विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में आयोजित किए जाएँगे।

इस बार लीग स्टेज में कुल 108 मुकाबले होंगे, जिसमें हर टीम 18 मैच खेलेगी।

'अब होगा संतुलन' सर्जियो गोर को भारत में यूएस एंबेसडर बनने पर शशि थरूर ने कही यह बड़ी बात

(जीएनएस)।

अमेरिका और भारत के कूटनीतिक रिश्तों में नई शुरूआत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक, सर्जियो गोर को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है।

गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस के निदेशक हैं और उन्हें दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। 38 वर्षीय गोर को ट्रंप के नजदीकी सहयोगी माने जाते हैं।

माना जा रहा है कि गोर की यह नियुक्ति भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नई मजबूती देगी और दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाएगी। हाल के दिनों में व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिला था।

थरूर ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इस नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि आखिरकार भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "किसी भी हाल में यह अच्छी खबर है कि अब भारत में अमेरिका का राजदूत मौजूद रहेगा।"

थरूर ने यह भी कहा कि अगर दक्षिण एशिया मामलों के लिए सहायक विदेश सचिव की नियुक्ति भी जल्दी हो जाए, तो दोनों देशों के बीच संवाद और अधिक स्थिर हो सकता है।

भारतीय मूल की उद्यमी आशा जाडेजा का बयान

भारतीय मूल की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जाडेजा मोटवानी ने अपने पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी को भारत का राजदूत बनाकर एक मजबूत संकेत दिया है। उनके अनुसार, गोर की नियुक्ति से भारत को सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंचने का मौका मिलेगा और वे स्पष्ट राय देंगे कि किन मुद्दों को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है।

भारत-अमेरिका संबंधों में नई उम्मीद

गोर की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब भारत-अमेरिका संबंध कुछ तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल था। ट्रंप प्रशासन ने इसका कारण भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बताया था।

हालांकि, गोर की नियुक्ति को भारतीय राजनयिक एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी और संचार को नया आयाम मिलेगा।

ट्रंप का बयान

राष्ट्रपति ट्रंप ने गोर को अपना "महान मित्र" बताते हुए कहा कि वे कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि मैं सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त कर रहा हूं।"

'उसका बाप उधर बैठा है', IND-PAK मैच पर संजय राउत की अपत्ति पर नितेश राणे ने किया पलटवार

एशिया कप के तहत होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जमकर हंगामा मचा हुआ है।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर आपत्ति जताई है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए अपने लेटर में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इस मैच पर कड़ी आपत्ति जताई। संजय राउत की इस आपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा उनकी पार्टी को संजय राउत जैसे लोगों से देश भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।

नमस्ते योजना के अंतर्गत अब तक 85,819 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों का प्रोफाइल तैयार - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य (नमस्ते) योजना के अंतर्गत 23 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान रोड, कारगिल चौक, पटना, बिहार में माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉ. वीरेंद्र कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

माननीय मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाले नमस्ते योजना के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 85,819 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है और 76,736 कर्मचारियों को पीपीई किट और 60,586 कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं।

पीपीई किट के महत्व और उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आकर्षक रंग परिधान कार्यक्रम (फैशन शो) का भी आयोजन किया गया। इसे सभी ने सराहा।

पटना में प्रोफाइलिंग के माध्यम से कुल 408 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों का सत्यापन किया गया। इनमें से 25 एसएसडब्ल्यू और 25 कचरा बीनने वालों को कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से पीपीई किट प्रदान की गईं और 25 सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। इसके अतिरिक्त ईआरएसयू के लिए सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए पर 11वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न

(जीएनएस)।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए) पर 11वें दौर की वार्ता 18-23 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को और बल मिला।

पिछले दौरों और अंतर-सत्रीय बैठकों में हुई प्रगति के आधार पर वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं और गतिशीलता, डिजिटल व्यापार, उत्पत्ति के नियम, कानूनी और संस्थागत प्रावधान, पर्यावरण, श्रम और लिंग सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। इससे शेष प्रावधानों में अभिसरण के लिए बेहतर समझ विकसित हुई।

दोनों पक्षों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि यह दोनों पक्षों के लिए सार्थक लाभ, आर्थिक अवसर और संतुलित परिणाम प्रदान करे। बातचीत में तेजी बनाए रखने और अभिसरण के लिए दोनों साझेदार वर्चुअल इंटरसेशन के माध्यम से वार्ता जारी रखेंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया भविष्य की ओर देखते हुए और भविष्य के लिए तैयार ढाँचे की दिशा में काम करने की साझा महत्वाकांक्षा और आपसी समझ के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग के शीघ्र समापन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। जैसे-जैसे भारत अनेक व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है, यह दौर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक आकांक्षाओं के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

सेना के जवान से अभद्रता करने के मामले में एनएचएआई की सख्ती, प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 17 अगस्त 2025 को मेरठ-करनाल सेक्शन (एनएच-709अ) स्थित भूनी टोल प्लाजा पर टोल स्टाफ द्वारा सेना के जवान से अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित टोल एजेंसी का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही, एजेंसी को एक वर्ष तक किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एनएचएआई ने इस टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी की 3.66 करोड़ रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त करते हुए भूनी टोल प्लाजा पर क्षतिग्रस्त हुए उपकरणों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत/प्रतिस्थापन लागत के लिए समायोजित किया जाएगा।

सम्पादकीय

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्रंप के सारे भ्रम किये दूर

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे भ्रम दूर करते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति आज हैं, वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा जो सार्वजनिक तरीके से विदेश नीति का निर्धारण और संचालन करता हो। इकोनामिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर का जवाब राष्ट्रपति ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो के इस वक्तव्य के ठीक बाद आया जब उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वह (यानि भारत) रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहा है, वही कारण है रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का।

इसलिए जब तक भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे लाभ कमाने के लिए शोधित करके बेचता रहेगा तब तक यूक्रेन के लोगों का खून बहता रहेगा। विदेश मंत्री ने नवारो की बकवास का जवाब देते हुए कहा कि भारत रूस से रियायती मूल्य पर कच्चा तेल खरीद कर तथा फिर परिष्वृत पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप और अन्य स्थानों पर ऊंची कीमतों पर बेच कर मुनाफाखोरी कर रहा है, का यह आरोप हास्यास्पद ही नहीं अजीब भी है।

उन्होंने कहा कि यदि आपको भारत से तेल या परिष्वृत पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में कोई समस्या है तो उसे न खरीदें। कोई आपको मजबूर नहीं करता। लेकिन यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए यदि आपको पसंद नहीं है तो उसे न खरीदें। सच तो यह है कि अमेरिका में जहां दोनों पार्टियों के नेता और अर्थशास्त्री ट्रंप के अज्ञानता पर यह कह कर सिर पीट रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ बने बनाए रिश्ते को बर्बाद कर दिया। निक्की हेली और बोल्टन की आलोचनाओं से तिलमिलाया नाटो कुछ भी कहे सत्य तो यही है कि अब ट्रंप प्रशासन एक बार फिर शीत युद्ध की तैयारी में है। इस बार लगता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ, शीत युद्ध लड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया नाटो और वारसा पैक्ट में बंट गईं तो दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गईं। यही जुबानी जंग शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। लगभग 5 दशक तक जो शीत युद्ध चला वह लोकतांत्रिक देशों यानि नाटो और साम्यवादी देश यानि वारसा पैक्ट के बीच सैद्धांतिक आधार पर छिड़ा था। लेकिन आज अमेरिका जिस तरह शीत युद्ध छेड़ने के लिए आमादा है, वह विशुद्ध रूप से व्यापारिक दादागिरी का परिणाम है। भारत को बाजार का टोटा नहीं है। इसलिए भारत अमेरिकी दादागिरी की परवाह भी नहीं करता। भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह उपभोक्ता आधारित है। ट्रंप आज तक इस वास्तविकता को नहीं समझ पाए कि यह दुनिया देखते ही देखते बहुध्रुवीय हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति आज भी दुनिया को द्विध्रुवीय ही मान रहे हैं तो इसमें उन देशों की कोई गलती नहीं है। जिनसे ट्रंप भिड़ रहे हैं। बहरहाल अमेरिकी प्रशासन के वुछ लाल बुझक्कड़ सलाहकारों के पास अपने देश के ही सामरिक विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की आलोचनाओं का जवाब देना नहीं आ रहा है तो भारत का कोई दोष नहीं है। लेकिन ट्रंप विरोधी अमेरिकी विशेषज्ञों की यह बात तो शत प्रतिशत सही है कि अब यदि ट्रंप प्रशासन टैरिफ में छूट दे भी दे तो भी नईं दिल्ली अमेरिकी प्रशासन पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि भारत अब अमेरिका के प्रति सतर्व हो गया है।

अगरतला में 'उप-राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी को सुदृढ़ बनाना' पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) के विकास तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य एवं जिला संकेतक रूपरेखाओं (एसआईएफ/डीआईएफ) के निर्माण में सहायता देने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया

कार्यशाला में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

(जीएनएस)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार ने त्रिपुरा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से 22 अगस्त 2025 को अगरतला, त्रिपुरा में 'उप-राष्ट्रीय एसडीजी निगरानी को मजबूत करने' पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया जो अभी भी अपने स्वयं के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचे को विकसित करने के प्रारंभिक चरण में हैं।

श्री बिकाश देबबर्मा, माननीय मंत्री, योजना (सांख्यिकी) विभाग, त्रिपुरा सरकार ने अपने उद्घाटन भाषण में रेखांकित किया कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के एक उपकरण के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक श्री एससी मलिक ने अपने भाषण में कहा कि निरंतर विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए स्थानीयकृत कार्रवाई और निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) विकसित करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य और जिला संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ/डीआईएफ) तैयार करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देने में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उच्च-गुणवत्ता, समय पर और विस्तृत डेटा की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि निगरानी अपने आप में एक अंत नहीं है श्री मलिक ने भारत में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों, संबंधित मंत्रालयों और भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री राजीव सेन ने अपने संबोधन में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निगरानी के माध्यम से संस्थानों को मजबूत करने और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर डाला। इसके बाद, त्रिपुरा सरकार के विशेष सचिव, योजना (सांख्यिकी) श्री अभिषेक चंद्रा ने अपने विशेष संबोधन में राज्य-स्तरीय डेटा प्रणालियों और स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निगरानी को मजबूत करके 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की। यूएनडीपी के प्रतिनिधि और नीति विशेषज्ञ श्री जैमन उत्थुप ने मजबूत डेटा प्रणालियों, तकनीकी क्षमताओं और समावेशी निगरानी तंत्रों के निर्माण में भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की संयुक्त निदेशक सुश्री सौम्या साक्षी और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उप निदेशक श्री अभिषेक गौरव ने राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) और उप-राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के माध्यम से भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी प्रणाली का अवलोकन प्रस्तुत किया। जो राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) और उप राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखाओं के माध्यम से किया जा रहा है एमओएसपीआई ने इस बात पर बल दिया कि राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उप-राष्ट्रीय स्तर पर (एसडीजी) की निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाया गया हैं। 2019 में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु अपने-अपने एसडीजी की निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें मार्च 2022 में अद्यतन कर और "उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी पर निगरानी ढांचे पर मार्गदर्शन" रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसआईएफ तैयार करने हेतु प्रेषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रतिनिधि ने स्थानीयकरण पर विशेष जोर देते हुए एसडीजी निगरानी में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं पर चर्चा की। इसके बाद, श्री चिरंजीव घोष, संयुक्त निदेशक, डीईएस त्रिपुरा ने राज्य संकेतक ढांचे (एसआईएफ) के विकास पर त्रिपुरा राज्य के अनुभव को साझा किया।

तकनीकी सत्रों का मुख्य उद्देश्य समूह अभ्यासों के माध्यम से राज्य की स्थिति का आकलन करना था, जिसका उद्देश्य प्रत्येक लक्ष्य की निगरानी के लिए प्रासंगिक संकेतकों की पहचान करना और मसौदा रूपरेखाएँ तैयार करना था। उन्होंने विभागीय ज़िम्मेदारियाँ सौंपकर, संकेतकों को प्राथमिकता देकर, और राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार करके कार्यान्वयन योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया, साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संकेतक ढाँचों में क्रॉस-कटिंग प्राथमिकताओं—विशेषकर लिंग और जलवायु संबंधी विचारों—को एकीकृत किया।

कार्यशाला का समापन सभी सहभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने उप-राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य निगरानी ढाँचों को मजबूत करने, स्थानीय विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे के साथ संरेखण सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करने के आ'ान के साथ हुआ। कार्यशाला में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और सतत विकास के 2030 एजेंडा के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

केरल के कुट्टनाड में मछली पालन को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र पायलट परियोजना शुरू करेगा

(जीएनएस)।

कोच्चिः केरल के कुट्टनाड में मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालकों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है। कोच्चि स्थित आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) में आयोजित एक बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

इस नई पहल के अंतर्गत भारत सरकार का मत्स्य विभाग, कुट्टनाड में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिक और पारंपरिक जलीय कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इनमें एकीकृत मत्स्य पालन, पिंजरे में मछली पालन, सतत "एक मछली एक धान" पहल और बायोफ्लोक मत्स्य पालन शामिल हैं।

इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए मत्स्य

कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन किया जाएगा।

मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों की आजीविका बढ़ाना इस पहल का प्रथम लक्ष्य है।

पायलट परियोजना के अंतर्गत किसानों को जलीय कृषि और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों में जरूरी कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। यह परियोजना स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी जो फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, सफाई, पैकिंग और मछली व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उपज का मूल्यवर्धन होगा।

कुट्टनाड के विविध जलीय वातावरण को देखते हुए इस परियोजना को मीठे और खारे पानी की खेती की अलग-अलग पहलों में विभाजित किया जाएगा जो विशेष रूप से ऊपरी और निचले कुट्टनाड की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय एजेंसियों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) सहित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इस पहल के तुरंत और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाएगी जिससे कुट्टनाड क्षेत्र को महत्वपूर्ण और स्थायी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मत्स्य विकास आयुक्त डॉ. मोहम्मद कोया, सीएमएफआरआई के निदेशक डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज और सीएमएफआरआई की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. इमेल्डा जोसेफ ने भी अपने विचार रखे जबकि विभिन्न शोध संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और केवीके के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

जेल में रह कर सरकार चलाना अब संभव न होगा

केंद्र सरकार द्वारा राजनीति में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से उठाया जाने वाला यह कदम स्वागतयोग्य है।

यदि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास करके लागू किया जाए तो यह पूरे विश्व में एक नजीर होता कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां अपने प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद को अपराधिक मामले में जेल जाने पर पद से हटा दिया जाता है।

जेल में रह कर सरकार चलाना अब संभव न होगा वुछ वर्ष पूर्व तक मैने एक लॉ के विद्यार्था, एक ब्यूरोव्रेट और लेखक स्तंभकार के रूप में यही जाना था कि यदि कोई व्यत्ति चौबीस घंटे से अधीक समाय के लिए जेल में होता है और किसी सरकारी पद पर आसीन हो जाता है तो उसे निलम्बित कर दिया जाता है और चार्ज शीट फाइल होने के बाद यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जाता है तो उच्च न्यायालय में दायर अपील का निस्तारण का इंतजार किए बगैर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाती है। पर मंत्रियो और सांसदो के लिए स्थिति अलग है जबकि न्यायालय ने कई पैसले मेरे इन्हें भी पब्लिक सर्वेट। माना हुआ है इन्हें उन्हीं की भांत वेतन मिलता है और उसके बाद पैंशन मिलती है। और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में लालवृष्ण आडवाणी ने एक ऐसा उच्च मानदंड स्थपित किया जो आज भी नैतिकता जीवनी में मिसाल के रूप में जाने जाता है, दषकों पहले हवाले कांड हुआ और उसमें अपना नाम आने पर संसद सदस्यों के रूप में त्याग पत्र दे दिया और राजनीतिक उत्तरदायित्व लेने से तब एक दूर रहे जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल गए। उसी प्रकार उस समय के दिली के मुख्यमंत्री रहे मदन लल खुरानी साहब ने हवाले में जैन डायरी में अपना नाम आने परअपना नाम आने पर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, यही नहीं चारा घोटाला में अपना नाम आने पर संभावित गिरफ्तारी से पूर्व बीहट के मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया और अपने स्थान पर अपनी पत्नी रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। पर यह प्रश्न कि की भी व्यत्ति जेल में रहने के बावजूद जेल से सड़कर चला सकता है तब खड़ा हुआ जब अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार उन्मूलन आन्दोलन से निकले अरविन्द केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया और जेल से ही सरकार चलाते रहे।

भविष्य में ऐसा न हो, ऐसी असहज स्थिति से निपटने के लिए वेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के मानसून सत्र समाप्त होने से दो दिन पूर्व लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसके अनुसार अगर प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, वेंद्र या राज्य के मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किए जाने है और वे जेल में तीस दिन से अधिक समय तक अंदर रहते हैं तो उन्हें तीस दिन के बाद अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। यद्दापि अभी तक ऐसा प्रावधान न होने के कारण अरविद केजरीवाल कई माह तक जेल से ही अपनी सरकारी चलाते रहे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था क्योंकि अरविद केजरीवाल जैसे कई नेता जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ते।

इस विधेयक को संवैधानिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है।

यह सही भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आवश्यकता है पर इस विधेयक के दुरुपयोग होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले वुछ समय से जांच एजेंसियों ईडी, आयकर विभाग, सी बी आई का दुरूपयोग विपक्षी के नेताओं के खिलाफ करने के आरोपी लगने लगे हैं। लेकिन इन संशोधनों से सत्तारूढ़ पक्ष के उन नेताओ पर भी खतरा मंडरा सकता है जो नेतृत्व के निदेर्शों की अनदेखी कर के स्वच्छंद रूप से कार्य करते हैं और जबसे वेंद्र और राज्य सरकारों में एलायंस पार्टनर्स के साथ सरकारें चल रही हैं तो इस

600 साल पुराना है इजराइल का राष्ट्रगान, दिलचस्प है इसके बनने की कहानी, हमास से भी है कनेक्शन

(जीएनएस)।

इजराइल के राष्ट्रगान "हतिकवाह" की कहानी बेहद जटिल और कई दिलचस्प किस्सों से भरी है। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि इतिहास, भावना और अनगिनत विवादों का संगम है। पियानोवादक और संगीतज्ञ एस्ट्रिथ बाल्टसन के अनुसार, हतिकवाह की हर परत में एक कहानी छिपी है, जो इसके अनंत इतिहास और भविष्य की उम्मीदों को दिखाती है।

इलान एवियातार ने 2010 में 'द जेरूसलम पोस्ट' में बाल्टसन के हवाले से ये बातें लिखी थीं। बाल्टसन ने "हतिकवाह - अतीत, वर्तमान, भविष्य" नामक पुस्तक लिखी है और "हतिकवाह - एक भजन का जन्म" शीर्षक से एक आकर्षक एकल शो भी प्रस्तुत करती हैं। यह राष्ट्रगान कई ऐसे तथ्यों को समेटे है जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है।

कौन थे हतिकवाह लिखने वाले नफ्ताली हर्ज इम्बेर?

हतिकवाह से जुड़ी कहानियों में कवि नफ्ताली हर्ज. इम्बेर का नाम सबसे ऊपर है। गैलिशिया (अब यूक्रेन) में 1856 में जन्मे इम्बेर ने नौ-छंदों वाली कविता "तिक्वातेनु" लिखी थी, जिसका पहला छंद ही आज हतिकवाह के रूप में गाया जाता है। 25 साल की उम्र में जब वे फिलिस्तीन के लिए निकले, तो उनकी जेब में एक अधूरी कविताओं वाली नोटबुक थी, जिसमें "तिक्वातेनु" भी शामिल थी।

कविता, प्यार और शराब

इजराइल स्टोरी पॉडकास्ट में, जेव लेवी बताते हैं कि इम्बेर रातों में स्थानीय लोगों के लिए अपनी कविताएं सुनाते थे, और दिन में, जब वे खेतों में काम करते थे, इम्बेर उनके वाइन सेलर पर छापा मारते थे। इम्बेर एक शराबी थे और 1887 में वे टूट चुके और नाखुश थे। बाल्टसन बताती हैं कि इम्बेर फिलिस्तीन छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने एक ईसाई महिला से शादी की, जिसने धर्म परिवर्तन किया था, फिर उन्हें तलाक दिया और शराब से होने वाली लीवर की बीमारी से गरीबी में 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

लिरिक्स और बदलाव

हतिकवाह के बोलों में समय के साथ बदलाव आया है। इम्बेर की मूल कविता में "हतिकवा हनोशाना, ल'एरेट्ज आवोटेनु, ला'इर बा डेविड क'हाना" (पुरानी आशा, हमारे पूर्वजों की भूमि पर लौटने की, उस शहर में जहां डेविड ने डेरा डाला था) लिखा था। 1895 में, हिब्रू भाषा समिति के संस्थापक डेविड येलिन और बाद में ऋषोन हिब्रू स्कूल के प्रधानाध्यापक लेइब मात्मोन कोहेन ने इन शब्दों को बदलकर वर्तमान स्वरूप दिया। हतिकवाह के बोल वास्तव में दो उपवाक्यों वाला एक जटिल वाक्य है।

600 साल पुरानी धुन और आधुनिक स्वीकार्यता

हतिकवाह की धुन को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है कि यह स्मेतना के 1874 के संगीत "डाई मोल्दाउ" से आई है। सच्चाई यह है कि हतिकवाह की धुन सदियों से दुनिया भर में यात्रा कर रही है, बिल्कुल डायस्पोरा यहूदियों की तरह। बाल्टसन ने पाया कि यह धुन 600 साल पुरानी है और सेफार्डी प्रार्थना "बिरकत हा'तल" से जुड़ी है।

इटली के गानों में हतिकवाह की धुन

इन्क्विज़िशन के बाद, जब यहूदी यूरोप में बिखर गए, तो यह धुन इटली तक पहुंची, जहां यह एक लोकप्रिय प्रेम गीत "फूगी, फूगी, अमोरे मियो" (भागो, भागो, मेरे प्यार!) बन गई। फिर यह एक रोमानियाई जिप्सी लोकगीत "कार्ट एंड ऑक्सन" में विकसित हुई। रोमानिया से फिलिस्तीन आए 17 साल के शमूएल कोहेन ने इस धुन का उपयोग हतिकवाह कविता के लिए किया, और यह तुरंत लोकप्रिय हो गई।

कई देशों से होकर लैंड ऑफ ज्यूस पहुंची धुन

स्मेतना के "डाई मोल्दाउ" से इसका संबंध कैसे जुड़ा? 12 साल के वुल्फगैंग एमेडीस मोजार्ट ने इटली में मूल लोक धुन सुनी थी, जहां उन्हें अध्ययन के लिए भेजा गया था। उन्होंने इसे अपनी एक रचना में शामिल किया, और इस संगीत को वियना, फिर प्राग ले गए। वहीं स्मेतना ने इसे अपनाया। स्मेतना का "डाई मोल्दाउ", हतिकवाह की तरह ही, एक राष्ट्रवादी विद्रोह का हिस्सा था। चेक संगीतकार का मानना था कि एक राष्ट्रीय आंदोलन एक नदी की तरह है; आप पानी को नहीं रोक सकते, ठीक वैसे ही जैसे आप आशा को बुझा नहीं सकते।

स्मेतना की सिम्फोनिक कविता "माई कंट्री", जिसमें "डाई मोल्दाउ" (वल्टावा नदी का जर्मन नाम, जो चेक गणराज्य की सबसे लंबी नदी है) शामिल है, बिना शब्दों के एक तरह का चेक राष्ट्रगान बन गया, बाल्टसन ने कहा। ब्रिटिश मैंडेट के दौरान, फिलिस्तीन में यहूदी रेडियो स्टेशन को हतिकवाह बजाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए रेडियो ने स्मेतना का "डाई मोल्दाउ" बजाया, क्योंकि ब्रिटिश शास्त्रीय संगीत के एक कार्य को प्रतिबंधित नहीं कर सकते थे।

तारीख- 10 नंबर 2004

हतिकवाह को आधिकारिक तौर पर 10 नवंबर, 2004 को ही इजराइल के राष्ट्रगान के रूप में "फ्लैग, कोट ऑफ आर्म्स एंड नेशनल एंथम लॉ" के तहत अपनाया गया। इसके पक्ष में निर्णायक वोट डुजे संसद सदस्य अय्यूब कारा ने दिया, जो डालीआत अल-कार्मेल से आते हैं और अब लिकुड के संचार मंत्री हैं। एक डुजे नागरिक हतिकवाह के पक्ष में क्यों वोट देगा?

एक वोट और तय हुआ राष्ट्रगान

इसका संबंध डुजे समुदाय से भी है। इम्बेर 1882 में कॉन्स्टेंटिनोपल (अब इस्तांबुल) में ब्रिटिश सांसद लॉरेंस ओलिफेंट से मिले थे। ओलिफेंट ने इम्बेर को अपना निजी सचिव बनाया और वे दोनों फिलिस्तीन के लिए निकले, जहां वे डुजे गांव डालीआत अल-कार्मेल में बस गए। इम्बेर का ओलिफेंट की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कारा के दादा ने ओलिफेंट के सहायक के रूप में काम किया था, इसलिए कारा ने इसके पक्ष में निर्णायक वोट दिया।

20 अप्रैल, 1945 को, ब्रिटिश यहूदी पादरी लेस्ली हार्डमैन ने बर्गन-बेलसन के बचे हुए लोगों को शिविर के बीच में खुले में एक कबालत शबात में नेतृत्व किया। बाल्टसन ने लिखा, "भूख से सूख चुके और मानव कंकालों जैसे दिखने वाले लोगों के समूह" ने "हतिकवाह को भयानक आवाजों में गाया"। इसे बीबीसी के एक रिपोर्टर ने रिकॉर्ड किया था और बाद में यह स्मिथसोनियन संस्थान की लाइब्रेरी में पाया गया। यह शायद हतिकवाह की सबसे मार्मिक और यादगार प्रारंभिक रिकॉर्डिंग में से एक है।

हतिकवाह से नफरत

हर्जल को हतिकवाह बिल्कुल पसंद नहीं था, शायद इसलिए कि वह इम्बेर को एक शराबी के रूप में जानते थे। 1903 में हर्जल ने एक राष्ट्रगान के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की, लेकिन प्रवेश करने वाले बहुत खराब थे। इजराइल स्टोरी के सह-संस्थापक मिशी हार्मोन ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व एमके उरी अवनेरी का साक्षात्कार लिया।

हर्जल की तरह, अवनेरी भी हतिकवाह से नफरत करते हैं। उन्होंने हार्मोन से कहा, "इसका इजराइल से कोई लेना-देना नहीं है। यह विदेशों में यहूदियों के बारे में है... और इसका इजराइल की भूमि के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक ऐसे राज्य के लिए अप्रासंगिक है जिसमें हमारी दो अलग-अलग आबादी हैं, यहूदी और अरब। हमें इस राष्ट्रगान से छुटकारा पाने और एक वास्तविक इजराइली राष्ट्रगान की आवश्यकता है।"

'द फेथ', एक और राष्ट्रगान

इजराइल राज्य की स्थापना से पहले के मुख्य रब्बी, रब्बी अब्राहम आइजैक कूक ने वास्तव में हतिकवाह के लिए एक वैकल्पिक राष्ट्रगान "द फेथ" लिखा था। इसके पहले दो छंद थेः "शाश्वत रूप से हमारे दिलों में रहती है, यह दृढ़ विश्वास कि हम अपनी पवित्र भूमि पर लौटेंगे, उस शहर में जहां डेविड बस गए। वहीं हम अपना भाग्य पूरा करेंगे, जिसे कई (राष्ट्रों) के पिता ने प्राप्त किया, वहीं हम अपना जीवन जिएंगे, अनेक लोगों के राष्ट्र का जीवन।"

इजरायली अरब और हतिकवाह

इजराइली अरबों के साथ हतिकवाह का संबंध भी जटिल है। लेवी बताते हैं कि 1976 में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय खेल में, जब हतिकवाह गाया गया, तो इजराइल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेलने वाले पहले इजराइली अरब खिलाड़ी रिफत तुर्क चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कहा, "मैं एक यहूदी आत्मा नहीं हूं। मैं एक अरब आत्मा हूं। यदि राष्ट्रगान के बोल मेरे जैसे लोगों के प्रति प्रेम और विचार के बारे में होते, तो मैं खुशी-खुशी इसे गाता।"

तुर्क को उनकी चुप्पी के लिए यहूदी प्रशंसकों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, खासकर कट्टरपंथी बीटर यरूशलेम समर्थकों द्वारा जब तुर्क की टीम हपोएल तेल अवीव ने बीटर के खिलाफ खेला था। उन्होंने चिल्लाया, "मैं तुम्हें मार डालूंगा।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

यात्रियों की सुविधा हेतु 29 अगस्त को भावनगर से बान्द्रा टर्मिनस के लिए चलेगी 'स्पेशल ट्रेन'

टिकटों की बुकिंग 24 अगस्त (रविवार) से शुरू होगी

पर्युषण पर्व के दौरान होने वाली भीड़ को समायोजित करने और यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर टर्मिनस और बांद्रा टर्मिनस के बीच विशेष किराए पर 'स्पेशल ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस विशेष ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः-

- ट्रेन नंबर 09210/09209 भावनगर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन नंबर 09210 भावनगर टर्मिनस-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल 29 अगस्त, 2025 (शुक्रवार) को भावनगर टर्मिनस से रात्रि 20.20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10.20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 09209 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल 30 अगस्त, 2025 (शनिवार) को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 13.50 बजे प्रस्थान करेगी और प्रातः 04.30 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भावनगर परा, सिहोर (गुजरात), सोनगढ़, धोला, बोटाद, सुरेन्द्रनगर गेट, विरमगाम, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, पालघर एवं बोरीवली स्टेशनों पर रूकेगी। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, शयनयान और द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्ं या 09210 एवं 09209 के लिए टिकटों की बुकिंग 24.08.2025 (रविवार) से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। इस ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के अवसर पर संबोधन

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली, पूसा में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम का विषय 'कृषि परिवर्तन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास' था। इस अवसर पर आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल जाट सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित रहें।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरी अत्यधिक इच्छा थी कि 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' का कार्यक्रम आईसीएआर में भी मनाया जाए।

अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से आज हम देश और दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि खेती में प्रौद्योगिकी और विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। हमें इसे और आगे बढ़ाना होगा।

श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। हमने अनाज उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं और इसमें हमारे अंतरिक्ष विज्ञान का अतुलनीय योगदान है। आज कृषि के क्षेत्र में किसानों की मदद करने में अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व उभरकर सामने आया है। क्रॉप आधुनिक महर्षि हैं। हमने खेती बदली है, खेती की दिशा बदली है, किसान की जिंदगी बदली है। जनता एवरेज प्रोडक्शन एस्टिमेशन का सवाल हो, फसल प्रणाली हो, गेहूं, धान, सरसों, कपास, गन्ना इत्यादि का उत्पादन, क्षेत्रफल का सटीक रूप से अनुमान लगाना या मौसम की जानकारी सहित अन्य विषय, सभी में अंतरिक्ष विज्ञान की अहम भूमिका है।

श्री चौहान ने कहा कि एक समय था जब कहावतों और मान्यताओं के आधार पर मौसम का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन आज इसरो द्वारा विकसित 'जियो पोर्टल' के माध्यम से सूखे-बारिश व मौसम की लगभग सटीक जानकारी मिलने लगी है, इसका जनता की जिंदगी में कितना महत्व है, इसका हम सभी को आभास है।

दादा निर्मल केसवानी की पुण्यतिथिः भोपाल में बच्चों को शिक्षण सामग्री, श्रद्धांजलि के साथ समाजसेवा की नई परंपरा

(जीएनएस)।

दादा निर्मल केसवानी भोपाल के एक ऐसे समाजसेवी थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में शिक्षा, एकता, और मानवता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी विचारधारा थी कि समाज का सच्चा उत्थान तभी संभव है, जब बच्चे शिक्षित और जागरूक हों। उनकी स्मृति में हर साल उनकी पुण्यतिथि पर शिक्षा और समाजसेवा से जुड़े आयोजन किए जाते हैं, जो उनकी विरासत को जीवित रखते हैं।

23 अगस्त 2025 को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल में निर्माण परिवर्तन संस्था ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बच्चों को किताबें, कॉपियां, पेंसिल, और अन्य शिक्षण सामग्री वितरित की गई। आयोजनकताओं ने बताया कि

जब बच्चों ने यह सामग्री प्राप्त की, तो उनके चेहरों पर आई मुस्कान दादा केसवानी के सपनों को साकार करने का प्रतीक थी।

निर्माण परिवर्तन के प्रतिनिधि ने बताया कि दादा केसवानी का मानना था कि शिक्षा समाज की असली पूंजी है। वे हमेशा बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहते थे। उनकी इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए संस्था ने हर साल पुण्यतिथि पर शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा शुरू की है। इस वर्ष के आयोजन में आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे-मुन्नों को शिक्षण सामग्री प्रदान कर उनकी पढ़ाई को आसान बनाने का प्रयास किया गया।

एक स्थानीय शिक्षक ने कहा, "दादा केसवानी की स्मृति में यह कार्यक्रम बच्चों के लिए नई राह खोल रहा है। यह छोटा सा प्रयास भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है।"

सुबह 10:30 बजेः शांति पाठ और हवन का आयोजन, जिसमें समाजसेवी, स्थानीय नागरिक, और दादा केसवानी के अनुयायी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दादा केसवानी की आत्मा की शांति और उनके आदर्शों को याद करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

शाम 6:00 बजेः भोपाल के शीतल दास की बगिया में झूलेलाल की फौज संस्था द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह भावनात्मक होगा, जहां दादा केसवानी के समाजसेवा के कार्यों को साझा किया जाएगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की योजनाओं पर चर्चा होगी।

आईएनएस तमाल ने ग्रीस की सौडा खाड़ी में बंदरगाह पर अपनी यात्रा पूरी की

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना का आधुनिकतम और उन्नत तकनीकों से लैस युद्धपोत आईएनएस तमाल भारत में अपने घरेलू बंदरगाह के लिए आने के मार्ग में 19-22 अगस्त, 2025 को ग्रीस के सौडा खाड़ी में रुका। बंदरगाह पर आगमन के दौरान भारतीय जहाज के चालक दल ने हेलेनिक नौसेना और नाटो अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसमें 19 अगस्त, 2025 को सौडा खाड़ी नौसेना बेस पर कमांडर कमोडोर डायोनिसियोस मंतादाकिस, नाटो समुद्री अवरोधन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र (एनएमआईओटीसी) के प्रमुख कैप्टन कोप्लाकिस इलियास और अमरीकी नौसेना के नौसेना सहायता गतिविधि के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन स्टीफन स्टीसी से कमांडिंग ऑफिसर की मुलाकात भी शामिल थी। बैठकों के दौरान चर्चा परिचालन संबंधी मामलों और समुद्री सहयोग पर केंद्रित रही। आईएनएस तमाल के चालक दल के लिए सौडा खाड़ी में इतालवी नौसेना के लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, बहु-भूमिका वाले हमले की इकाई आईटीएस ट्राइस्टे पर एक क्रॉस डेक दौरा आयोजित किया गया।

ग्रीस में भारत के राजदूत रुद्रेन्द्र टंडन ने 20 अगस्त, 2025 को जहाज का दौरा किया और चालक दल के साथ बातचीत की। चालक दल ने युद्धपोत के बंदरगाह प्रवास के दौरान, सौडा नौसेना बेस और आयुध सुविधा, एनएमआईओटीसी और स्थानीय समुद्री संग्रहालय का दौरा किया। जहाज के चालक दल ने क्रेते में द्वितीय विश्व युद्ध के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित की।

आईएनएस तमाल 22 अगस्त, 2025 को सौडा खाड़ी से रवाना हुआ और उसने हेलेनिक नौसेना की रूसेन श्रेणी की गश्ती नौका एचएस रिटोस के साथ एक अभ्यास में भाग लिया, जिसका उद्देश्य नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता को बढ़ावा देना था।

आईएनएस तमाल का बंदरगाह पर आगमन भारत द्वारा ग्रीस के साथ अपने संबंधों को दिए जाने वाले महत्व और दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को सशक्त करने के प्रयासों को दशार्ता है। इसने दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और संयुक्त सहयोग के लिए

'अगर गृह मंत्री उस फैसले को', अमित शाह के आरोपों पर राष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दिया जवाब

(जीएनएस)।

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भाजपा ने एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बताया है और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाय है।

विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस आरोप पर कि कांग्रेस ने "नक्सलवादी सोच" वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है (क्योंकि रेड्डी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा थे जिसमें सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराया गया था)। शाह के इस आरोप पर सुदर्शन रेड्डी ने अब खुलकर जवाब दिया है।

आज तक को दिए इंटरव्यू में विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपनी उम्मीदवारी को सैद्धांतिक प्रतिस्पर्धा" बताया है। उन्ं होंने साफ किया कि वो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं और न ही ऐसा करने का उनका कोई इरादा है।

अमित शाह के आरोप का जवाब देते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा "सलवा जुडूम पर दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, केवल मैंने लिखा था। यह मेरा व्यक्तिगत जजमेंट नहीं था। अगर गृह मंत्री उस फैसले को पढ़ लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"

सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह से

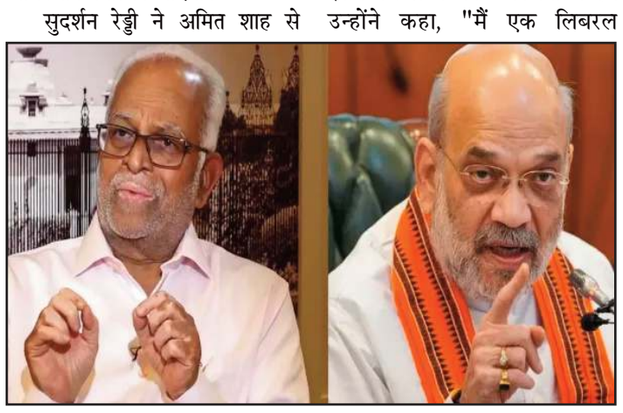

सवाल किया कि वे इतने सालों तक चुप क्यों रहे। उन्होंने कहा, "मैं यहीं भारत में था, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नक्सलवाद मेरे कारण खत्म नहीं हुआ। अब वह इसे मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें हक है, बना सकते हैं। लेकिन इतने साल तक चुप क्यों रहे?"

सुदर्शन रेड्डी बोले- एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट हूं

सुदर्शन रेड्डी ने कहा उपराष्ट्रपति का चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा नहीं सांसदों द्वारा किया जाता है। उन्ं होंने कहा मेरी विचारधारा पूरी तरह से भारतीय संविधान पर आधारित है। उन्होंने बताया कि वे 50 से अधिक वर्षों से संविधान की एक प्रति अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें हर प्रश्न का उत्तर निहित है। उन्होंने कहा, "मैं एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट हूं और मेरा विश्वास सिर्फ संविधान पर है।"

दो दक्षिण भारतीयों के बीच मुकाबले पर क्ं या बोले सुदर्शन रेड्डी

"संघ बनाम संविधान" की बहस पर टिप्पणी करते हुए, जिसे विपक्ष ने इस चुनाव के मुख्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया है, रेड्डी ने कहा कि यह किसी राज्य की पहचान या "तेलुगु प्राइड बनाम तमिल प्राइड" का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, "हम सब भारतीय नागरिक हैं। किसी का तमिलनाडु में जन्म हुआ और मेरा तेलंगाना में, इसमें गर्व या प्रतिस्पर्धा जैसी कोई बात नहीं है।"

चंद्रबाबू नायडू के रुख पर क्या बोले सुदर्शन?

चंद्रबाबू नायडू के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए, रेड्डी ने स्वीकार किया कि तेलुगु देशम पार्टी "तेलुगु प्राइड" के नारे के साथ बनी थी, लेकिन मौजूदा उपराष्ट्रपति चुनाव को इस संदर्भ में देखना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि वे सभी दलों के सांसदों से समर्थन मांगेंगे क्योंकि वे किसी एक दल के प्रतिनिधि नहीं हैं।

सुदर्शन बोले- मैं एनडीए सांसदों से वोट की अपील करूंगा

समर्थन जुटाने की अपनी कोशिशों के बारे में रेड्डी ने बताया कि विपक्षी दलों के अलावा, वे बीआरएस और वाईएसआरसीपी जैसे क्षेत्रीय दलों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं सभी सांसदों को लिखूंगा, चाहे वे किसी भी दल के हों, यहां तक कि एनडीए सांसदों को भी अपील करूंगा कि वे मुझे वोट दें।"

मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे

पिछली बार गोपालकृष्ण गांधी को क्रॉस वोटिंग के कारण कम वोट मिलने की स्थिति पर जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बार भी वही स्थिति रहेगी, तो रेड्डी ने कहा, "मैं इस पर अटकलें नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे।"

'स्वास्थ्य कोई सीमा नहीं जानता; सहयोग लचीला चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र की कुंजी है': श्री अमित अग्रवाल, सचिव, फार्मास्यूटिकल्स विभाग

श्री अमित अग्रवाल ने कहा, भारत वैश्विक मेडटेक केंद्र के रूप में उभरने की नींव रख रहा है

(जीएनएस)।

श्री अमित अग्रवाल, सचिव, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने कल 'मेडिकल-टेक नवाचारों के लिए अंतर-क्षेत्रीय नेटवर्किंग का लाभ उठाना' सत्र की अध्यक्षता की। यह दो दिवसीय दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बैठक 'सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचारः रिसर्च प्लेटफॉर्म पर अच्छे प्रथाओं का आदान-प्रदान' के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सत्र में भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और तिमोर-लेस्ते की सरकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के वरिष्ठ स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणालियों को मजबूत करने, अच्छे प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया। बैठक दक्षिण

और दक्षिण पूर्व एशिया स्वास्थ्य अनुसंधान (रिसर्च) प्लेटफॉर्म के लिए क्षेत्रीय प्रवर्तक का हिस्सा है

सत्र को संबोधित करते हुए, औषधि विभाग के सचिव, श्री अमित अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि "स्वास्थ्य की कोई सीमा नहीं होती"। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने लचीली और मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ बनाने के लिए, सीमाओं के पार, विभिन्न क्षेत्रों के बीच, सरकारी विभागों और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दशार्या है।

श्री अग्रवाल ने केवल तकनीक और कुशल जनशक्ति के माध्यम से, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना, वैश्विक रूप से सुसंगत मानकों को अपनाने और नवीन उपकरणों के लिए नैदानिक जांच को समर्थन देकर, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएँ हासिल की जा सकें और राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी मांग को बढ़ाया जा सके। भारत में चिकित्सा उपकरण पार्कों के निरंतर विकास और आईसीएमआर की मेडटेक मित्र और पेटेंट मित्र पहलों, नैदानिक परीक्षण सहायता योजनाओं और मजबूत अनुसंधान प्लेटफार्मों के साथ, भारत व्यवस्थित रूप से एक महत्वपूर्ण मेडटेक नवाचार केंद्र के रूप में उभरने की नींव रख रहा है।

सचिव ने कुशल मानव पूंजी के विकास में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के योगदान पर भी प्रकाश डाला। चिकित्सा उपकरणों पर विशेष पाठ्यक्रम अब सात एनआईपीईआर में चलाए जा रहे हैं, और इन्हें विदेशी नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से चिकित्सा प्रौद्योगिकियाँ अस्पतालों से घरों तक पहुँचेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और सस्ती हो जाएगी। उन्होंने औषधि विभाग द्वारा विकसित "अकादमिक से उद्योगः डिस्कवरी मार्केटप्लेस" प्लेटफॉर्म के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य उद्योग, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और फार्मा-मेडटेक क्षेत्र के अन्य हितधारकों को नवीन उत्पादों के लिए साझेदारी, सहयोग और गठजोड़ के लिए जोड़ने में सक्षम बनाना और वाणिज्यिक और सार्वजनिक हित दोनों के लिए सफलताओं को बढ़ावा देना है।

अब वंदे भारत जैसी ट्रेन में नहीं होंगे लोको पायलट!

(जीएनएस)।

लखनऊ में रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने एक एआई सेल बनाया है। यह सेल ट्रेनों के संचालन सुरक्षा और क्रू प्रबंधन में एआई के इस्तेमाल की संभावनाओं पर विचार करेगा। बताया जा रहा है कि वंदे भारत समेत कई ट्रेन में इस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। इससे लोको पायलट पर निर्भरता खत्म हो सकती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बाद हो सकता है कि भविष्य में बिना लोको पायलट के ट्रेन दौड़ती हुए दिखेगी। भविष्य में ट्रेनों के आपरेशन में एआई की मदद कैसे ली जा सकती है? इसका पता लगाने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने पहल की है। रेलवे ने आपरेटिंग एआई सेल बनाया है।

बदलेगी रेलवे की तस्वीर

मेट्रो सेवाओं में ड्राइवर के बिना

ट्रेन दौड़ाने की तकनीक पहले ही आ चुकी है। रेलवे में आइआरसीटीसी फिलहाल एआई का उपयोग यात्रियों के सवालों के जवाब देने के लिए कर रहा है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों के फीचर एआई को सपोर्ट कर सकते हैं। सेमी हाइस्पीड ट्रेनों की कैब सिग्नलिंग प्रणाली को और आधुनिक किया जा रहा है। लखनऊ से कानपुर के बीच जो 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की क्षमता वाला ट्रैक बिछाया जा रहा है, उसमें भी लोको पायलट को उनके क्रू केबिन में ही सिग्नल और पटरियों पर आने वाले अवरोध बहुत दूर से दिखाई देंगे। इतना ही नहीं कवच प्रणाली आने से एक पटरी पर आयी ट्रेनों की टक्कर की घटना भी रुक सकेगी।

कैब सिग्नलिंग और अपने आधुनिक हो रहे माइक्रोप्रोसेसर यूनिट को एआई से लिंक करने के लिए रेलवे ने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले रेलवे फिलहाल स्टेशनों पर ट्रेनों के खाली रेक की शंटिंग और लोको पायलटों की ड्यूटी लगाने वाले क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में एआई का उपयोग करेगा। रेलवे का यह ट्रेन आपरेशन के लिए अपनी तरह का पहला एआई सेल बनाया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सेल में सभी आपरेटिंग मैन्यूअल में एआई उपयोग को लेकर रिसर्च चल रही है। साफ्टवेयर से जुड़े कुछ विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। एक बार पायलट प्रोजेक्ट का माडयूल तैयार हो जाएगा तो सेंटर फार रेलवे इंफारमेशन सिस्टम (क्रिस) और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ इसका प्रस्तुतिकरण होगा।

भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिले वोटर लिस्ट में, गृह मंत्रालय की जांच से हड़कंप

(जीएनएस)।

बिहार में विपक्षी दल वोटर संशोधन लिस्ट (रक्फ) पर सरकार को घेर रहे हैं। चुनाव में अनियमितता और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दल के नेता वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इधर वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे विदेशियों जांच शुरू कर दी थी। इसी प्रक्रिया के दौरान तीन पाकिस्तानी नागरिकों के भागलपुर में रहने की पुष्टि हुई है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर में दो महिलाओं समेत तीन पाकिस्तानी नागरिकों के मिलने की पुष्टि हुई है। गृह मंत्रालय की जांच से हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय की ओर से की गई जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम भागलपुर की मतदाता सूची में दर्ज हो गए थे और उन्हें वोटर आईडी कार्ड भी जारी कर दिए गए थे।

SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के दावों के बीच चौंकाने वाली खबर

बिहार में वोटर संशोधन लिस्ट प्रक्रिया में गड़बड़ी का दावा विपक्षी दल समेत कई एनजीओ भी कर रहे हैं। इस बीच भागलपुर जिले में तीन पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की पुष्टि हुई है। इनमें दो महिलाएं -इमराना खानम उर्फ इमराना खातून, फिरदौसिया खानम का नाम सामने आया है।

जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि ये दोनों महिलाएं भारत में रह रही हैं, लेकिन इनकी नागरिकता में परिवर्तन नहीं आया था। इन्हें वोटर कार्ड जारी कर दिया गया है और इससे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। वोटर लिस्ट संशोधन पर विपक्षी दल गड़बड़ियों का दावा कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी रह सकती है।

जिलाधिकारी ने दिया कार्रवाई का आदेश

क्राइम ब्रांच की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। भागलपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि दोनों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की जानकारी हमें मिली है। इसे सूची से हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे संज्ञान में यह मामला आया है। इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह जांच का विषय है कि किसकी लापरवाही से ये तीन पाकिस्तानी नागरिकों के नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कूलस्कल्प्टिंग से मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया

सीसीपीए ने भविष्य में विज्ञापनों पर तथ्यों की सटीक जानकारी (स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर) देने करने का आदेश दिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने यूएस-एफडीए अनुमोदित कूलस्कल्प्टिंग प्रक्रिया/मशीन के उपयोग के माध्यम से मोटापा घटाने और स्लिमिंग उपचार के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है।

इससे पहले, सीसीपीए ने कूलस्कल्प्टिंग उपचारों पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए काया लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया था। कंपनी के विज्ञापनों में दावा किया गया था कि "काया का नॉन-सर्जिकल फैट रिडक्शन" और "काया कूलस्कल्प्टिंग से आसानी से वजन घटाता है"। विज्ञापनों पहले और बाद की भ्रामक तस्वीरें भी दिखाई गई थी, जो पूरे शरीर में भारी मात्रा में फैट कम होने का संकेत दे रही थीं। ये दावे वास्तविक अमेरिकी-एफडीए अनुमोदन से परे थे और इस प्रक्रिया को वजन घटाने के उपचार के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।

काया लिमिटेड ने सीसीपीए के आदेश का अनुपालन किया है और जुमार्ना राशि जमा कर दी है।

वीएलसीसी लिमिटेड का मामला सीसीपीए के संज्ञान में एक शिकायत और स्लिमिंग एवं सौंदर्य क्षेत्र में विज्ञापनों की निगरानी के माध्यम से आया। जांच करने पर पाया गया कि वीएलसीसी एक ही सत्र में भारी वजन घटाने और इंच कम करने का अतिशयोक्तिपूर्ण दावा कर रही थी, जो कूलस्कल्प्टिंग मशीन को दी गई वास्तविक स्वीकृति से कहीं अधिक था, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे थे।

जांच से पता चला कि वीएलसीसी के विज्ञापनों में कूलस्कल्पटिंग और संबंधित प्रक्रियाओं को स्थायी वजन घटाने और आकार घटाने के समाधान के रूप में पेश किया गया था। कुछ कथित दावे इस प्रकार हैं:

'एक सत्र में 600 ग्राम और 7 सेमी तक वजन कम करना'

'एक सत्र में 1 साइज स्थायी रूप से कम करना'

'एक घंटे में एक साइज तक कम करना'

"वीएलसीसी लेकर आया है एक अभूतपूर्व मोटापा घटाने वाला उपचार"

"लिपोलेजर से एक सत्र में ही 6 सेमी और 400 ग्राम वजन कम करना"

ऐसे विज्ञापनों से उपभोक्ताओं के बीच गलत धारणा बनी कि कूलस्कल्प्टिंग स्थायी और महत्वपूर्ण वजन घटाने की गारंटी है। वास्तव में, यह प्रक्रिया केवल शरीर के कुछ विशिष्ट भागों में मौजूद वसा में कमी के लिए तथा केवल 30 या उससे कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों के लिए ही स्वीकृत है।

यूएस-एफडीए अनुमोदित कूलस्कल्पटिंग मशीन के संबंध में सीसीपीए ने पाया कि:

जेल्टिक एस्थेटिक्स द्वारा निर्मित कूलस्कल्प्टिंग मशीन को यूएस-एफडीए द्वारा केवल अपर आर्म, ब्रा फैट, बैक फैट, बनाना रोल फैट, सबमेंटल एरिया, जांघ, पेट और फलैंक जैसे भागों में मौजूद वसा को कम करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

यह वजन घटाने का उपचार नहीं है।

यूएस-एफडीए को प्रस्तुत किए गए नैदानिक परीक्षणों में कॉकेशियन, हिस्पैनिक और अफ्रीकी अमेरिकी जातीयता के केवल 57

2040 में एक भारतीय चंद्रमा की सतह से 'विकसित भारत 2047' की घोषणा करेगा और इससे पूरे ब्रह्मांड में यह संदेश जाएगा कि भारत पहुंच गया है: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

विज्ञान, कविता, यथार्थवाद और भविष्य की संभावनाओं से युक्त अपने भाषण में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि एक भारतीय 2040 में चंद्रमा की सतह से "विकसित भारत 2047" की घोषणा करेगा और इससे पूरे ब्रह्मांड में यह संदेश जाएगा कि भारत आ गया है।

यहाँ भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, शुरू से ही, रॉकेट और उपग्रहों से कहीं आगे रहा है - यह लोगों को सशक्त बनाने, जीवन को बेहतर बनाने और एक बेहतर भविष्य को आकार देने के बारे में रहा है। उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय मीट 2.0 का भी उल्लेख किया, जो 2015 में पहले मेगा यूजर मीट के एक दशक बाद आयोजित किया गया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस बात की याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियाँ अपने आप में एक लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण की ओर एक कदम हैं— जहाँ विज्ञान, नवाचार और जन कल्याण मिलकर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं।" उन्होंने गगनयान मिशन की तैयारी कर रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप की ओर इंगित करते हुए कहा कि इसरो ने भारत के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति बनाई है।

2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शासन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करने के आ'ान को याद करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2015 ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को प्रमुख विकास कार्यक्रमों में एकीकृत करने का दृष्टिकोण निर्धारित किया था।

भारतीय नौसेना का जहाज कदमत्त सुराबाया बंदरगाह पर पहुंचा

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कदमत्त ने इंडोनेशिया के सुरबाया में तीन दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसके प्रवास से भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना (टीएनआई एएल) के बीच मैत्री, विश्वास एवं आपसी सहभागिता को विस्तार मिला है।

यात्रा के दौरान, समुद्री सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख गतिविधियों में कार्यात्मक संवाद और क्रॉस-डेक दौरे शामिल थे - जिससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ावा मिला है।

चालक दल ने जहाज पर संयुक्त योग सत्र और टीएनआई एएल कर्मियों के साथ एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच में भी भाग लिया, जिससे सौहार्द व सहयोग की साझा भावना प्रदर्शित हुई।

इस जहाज ने सामुदायिक पहुंच के एक भाग के रूप में इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों का स्वागत किया, उन्हें जहाज पर आने और चालक दल के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व के साथ शिष्टाचार भेंट ने क्षेत्र में सुरक्षित एवं स्थिर समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में मिलकर काम करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता पर और अधिक बल दिया।

आईएनएस कदमत्त की यात्रा ने इस क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में भारतीय नौसेना की भूमिका की पुष्टि की और 'समुद्र पार साझेदारी' के साझा दृष्टिकोण के तहत भारत तथा इंडोनेशिया के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी को सशक्त किया।

केरल के कुट्टनाड़ में मछली पालन को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र पायलट परियोजना शुरू करेगा

(जीएनएस)।

कोच्चिः केरल के कुट्टनाड में मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालकों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है। कोच्चि स्थित आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) में आयोजित एक बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

इस नई पहल के अंतर्गत भारत सरकार का मत्स्य विभाग, कुट्टनाड में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आधुनिक और पारंपरिक जलीय कृषि पद्धतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इनमें एकीकृत मत्स्य पालन, पिंजरे में मछली पालन, सतत "एक मछली एक धान" पहल और बायोफ्लोक मत्स्य पालन शामिल हैं।

इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन किया जाएगा।

मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि इस क्षेत्र के किसानों की आजीविका बढ़ाना इस पहल का प्रथम लक्ष्य है।

पायलट परियोजना के अंतर्गत किसानों को जलीय कृषि और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों में जरूरी कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। यह परियोजना स्टार्टअप्स को इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी जो फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे प्रसंस्करण, सफाई, पैकिंग और मछली व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उपज का मूल्यवर्धन होगा।

कुट्टनाड के विविध जलीय वातावरण को देखते हुए इस परियोजना को मीठे और खारे पानी की खेती की अलग-अलग पहलों में विभाजित किया जाएगा जो विशेष रूप से ऊपरी और निचले कुट्टनाड की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय एजेंसियों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) सहित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इस पहल के तुरंत और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तुरंत तैयार की जाएगी जिससे कुट्टनाड क्षेत्र को महत्वपूर्ण और स्थायी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मत्स्य विकास आयुक्त डॉ. मोहम्मद कोया, सीएमएफआरआई के निदेशक डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज और सीएमएफआरआई की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. इमेल्डा जोसेफ ने भी अपने विचार रखे जबकि विभिन्न शोध संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और केवीके के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एकजुट हुए

(जीएनएस)।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) ने कल नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को मजबूत करने पर एक उच्च-स्तरीय क्षेत्रीय संवाद के लिए भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तिमोर-लेस्ते और भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया। यह बैठक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य अनुसंधान सीधे नीति निर्माण को प्रभावित करे, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को समाधान करे और भविष्य के लिए दीर्घकालिक प्रणालियो के निर्माण में सहायक बने।

विचार-विमर्श में प्रख्यात विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही सत्रों की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, प्रोफेसर प्रो. डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की सदस्य डॉ. शमिका रवि, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के सीईओ डॉ. शिवकुमार कल्याणरमन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री राजेश भूषण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने की।

मेड-टेक नवाचार में भारत की प्रगति को साझा करते हुए, इस विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता करते हुए, औषधि विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के मानद विशिष्ट फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के मानद विशिष्ट

क्या प्रधानमंत्री को छूट दी जाएगी? पीएम, सीएम व मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर अपराधों के लिए जेल जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित विधेयकों में खुद को छूट देने से इनकार कर दिया। इन विधेयकों के मसौदे पर सरकार काम कर रही थी।

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल को सूचित किया था कि इन विधेयकों के दायरे से प्रधानमंत्री को बाहर रखने की सिफारिश की गई है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस सिफारिश से असहमति जताई।

रिजिजू ने एएनआई को दिए अपने बयान में कहा, "पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल से कहा कि सिफारिश है कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक से बाहर रखा जाए, लेकिन वह इससे सहमत नहीं थे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री को कोई विशेष छूट देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं, और उन्हें कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "अधिकांश मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से हैं। यदि वे कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि विपक्ष नैतिकता को केंद्र में रखता, तो वे इस विधेयक का स्वागत करते।"

भाजपा का मत है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए लाए गए नए विधेयक नैतिकता और ईमानदारी सुनिश्चित करेंगे। इन प्रस्तावित विधेयकों में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों का शासन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

इन विधेयकों में प्रावधान है कि यदि किसी मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री को ऐसे अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, जिसमें पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा का प्रावधान है, तो वे एक महीने के भीतर अपना पद खो सकते हैं।

ये विधेयक अमित शाह द्वारा विपक्षी विरोध और नारेबाजी के बीच पेश किए गए थे। विरोध इतना तीव्र था कि विधेयक के मसौदे को फाड़ दिया गया और उसके टुकड़े केंद्रीय गृह मंत्री पर फेंके गए। हालांकि, बाद में इन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया।

विपक्षी नेताओं ने इन विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों को "कठोर" और "असंवैधानिक" करार दिया है। उनका आरोप है कि इन विधेयकों का उपयोग केंद्रीय एजेंसियों के इशारे पर विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।

उज्जैन में लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई: सहायक सचिव भगवान सिंह सोंधिया 11,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों

(जीएनएस)।

19 अगस्त 2025 को ग्राम कंवराखेड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा निवासी राजेश दांगी ने उज्जैन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार यादव से शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि उनके भाई बालचंद दांगी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी पहली किस्त 25,000 रुपये प्राप्त हो चुकी थी।

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने सोंधिया के खिलाफ जाल बिछाया। 23 अगस्त 2025 को उज्जैन के शनि मंदिर परिसर में ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई, जिसमें भगवान सिंह सोंधिया को राजेश दांगी से 11,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत की राशि उनकी पेंट की जेब से बरामद की गई। यह कार्रवाई निदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई।

लोकायुक्त की ट्रैप टीम

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल
निरीक्षक हिना डावर
कार्यवाहक प्रधान आरक्षक हितेश ललावत
आरक्षक श्याम शर्मा
सहायक ग्रेड-3 रमेश डावर
आरक्षक संदीप राव कदम

आरक्षक उमेश जाटव

इस टीम ने सटीक योजना और समन्वय के साथ ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप भगवान सिंह सोंधिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

मामले का विवरण

शिकायतकर्ता राजेश दांगी ने बताया कि उनके भाई बालचंद दांगी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की दूसरी किस्त जारी करने के लिए सहायक सचिव भगवान सिंह सोंधिया ने 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। सोंधिया ने पहले ही 4,000 रुपये शिकायत सत्यापन के दौरान ले लिए थे और बाकी 11,000 रुपये की मांग कर रहे थे। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की गोपनीय जांच की, जिसमें सोंधिया के रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद, 23 अगस्त को उज्जैन के शनि मंदिर परिसर में ट्रैप कार्रवाई की गई, जहां सोंधिया को 11,000 रुपये लेते पकड़ा गया।

लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत सोंधिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है, और आगे की जांच जारी है।

स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया। एक ग्रामवासी ने कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं में रिश्वतखोरी गरीबों के हक को छीनती है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में डर पैदा होगा।"

विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन साथ ही मांग की कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएं। एक कांग्रेस नेता ने कहा, "यह एक अच्छी शुरूआत है, लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयां नियमित रूप से हों और ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार पर और नजर रखी जाए।"

लोकायुक्त की सख्त नीति

निदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख ने हाल के महीनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उनकी देखरेख में उज्जैन, भोपाल, और अन्य क्षेत्रों में कई ट्रैप कार्रवाइयां की गई हैं। इस कार्रवाई से पहले, 11 अगस्त 2025 को उज्जैन में ही चिमनगंज थाने के एक आरक्षक को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार यादव ने कहा, "हमारी टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

पीएम मोदी का दावा- 2025 के अंत तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, 6जी पर भी दिया अपडेट

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के भविष्य पर शनिवार को बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने दशकों पहले इस क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर गंवा दिया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि भारत में निर्मित पहला सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगा। इसके बलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार 'मेड-इन-इंडिया' 6ङ्क नेटवर्क के विकास पर तेजी से काम कर रही है।

द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी (फाइल फोटो/रॉयटर्स) ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर निर्माण भारत में 50-60 साल पहले शुरू हो सकता था, लेकिन भारत वह मौका चूक गया और यही स्थिति कई सालों तक बनी रही। आज हमने इस स्थिति को बदल दिया है। सेमीकंडक्टर से संबंधित कारखाने भारत में आने लगे हैं।"

मोदी ने इस बात को दोहराया कि पहला स्वदेशी चिप इस साल के अंत तक उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा, "इस साल के अंत तक, पहला 'मेड इन इंडिया' चिप बाजार में आ जाएगा।" उन्होंने दूरसंचार प्रौद्योगिकी में चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

प्रधान मंत्री ने कहा, "हम 'मेड इन इंडिया' 6ङ्कपर तेजी से काम कर रहे हैं," जो वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल बिठाने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन (एव) क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि देश 100 देशों को ईवी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, "मैं आपको भारत की एक और सफलता के बारे में बताना चाहता हूं। भारत अब दुनिया के 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने जा रहा है। इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 2 दिनों के बाद 26 अगस्त को भी आयोजित किया जा रहा है।"

बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए, मोदी ने कहा, "भारत, जो 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' के मंत्र का पालन करता है, आज दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालने की स्थिति में है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो रुके हुए पानी के किनारे बैठकर पत्थर फेंकते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो तेज बहने वाली धारा को मोड़ सकते हैं।"